



Ref: 381/2021
Dt-23-9-2021

आदरणीय मंत्री महोदय,

विषय—बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति के अनुरूप तेल कम्पनियों द्वारा मिथिला क्षेत्र में बंद पड़ी 4 चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने के संबंध में।

माँ सीता की जन्म भूमि मिथिला के प्रति आपका स्नेह पूर्व से ही विद्यमान है। आपकी महती कृपा एवं सार्थक प्रयास से ही मिथिला को हवाई मार्ग भी मिल गया है। दरभंगा हवाई अड्डे से देश के अन्य शहरों का उड़ान सेवा प्रारंभ है तथा सफलतापूर्वक परिचालन से आमजनों में उत्साह है। इस कार्य से मिथिला के विकास में एक नई संभावना की शुरुआत हुई है।

मैं आपका ध्यान मिथिला क्षेत्र को इथेनॉल हब के रूप में विकसित करने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करावाली कई अन्य दूसरी फसल, मक्का एवं चावल आदि से भी तैयार किया जा सकता है, जो मिथिला में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह खेती और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। दरभंगा, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडल से युक्त मिथिला क्षेत्र 90 के दशक तक गन्ना की उपज के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण इस क्षेत्र में चार चीनी मीलों स्थापित थी। यह क्षेत्र मक्का के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। यहां अपार जल संसाधन मौजूद है, साथ ही श्रम संसाधन की कमी भी नहीं है।

यातायात हेतु सड़क मार्ग में पोरबंदर(गुजरात) से चलकर सिलचर(असम) जानेवाली ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर में एन.एच. 57 (मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक जानेवाली) राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है। मिथिला को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं अन्य प्रमुख सड़कें बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारतीय रेल के प्रयास से मिथिला रेल नेटवर्क से जुड़ते हुए अलग पहचान बना रही है एवं रेल मंत्रालय द्वारा अमान परिवर्तन के साथ अन्य रेल संबंधी कार्य सुचारु रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अधीन मिथिला में बंद पड़े चीनी मिलों में भारतीय तेल कम्पनियों द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने से मिथिला इथेनॉल हब बनने के साथ-साथ रोजगार के लिए सुलभ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई होगी।

देश की तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) ने राज्यों के लिए इथेनॉल का कोटा निर्धारित किया है, जिसमें बिहार के लिए 18 करोड़ लीटर प्रति वर्ष (दिनांक 1 दिसंबर से आगामी 30 नवंबर तक) शामिल है। इथेनॉल के वृहद उत्पादन से बिहार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ झारखंड एवं पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इथेनॉल उपलब्ध करा सकता है।

इथेनॉल खरीद के लिए तेल कंपनियों द्वारा जारी टेंडर में देश के 197 प्रस्तावित इथेनॉल इकाईयों में 29 प्रस्ताव बिहार से हैं। बिहार की प्रस्तावित इकाईयों ने सलाना 187 करोड़ लीटर

इथेनॉल सप्लाई की दावेदारी पेश की है। बड़े हर्ष की बात है कि एन.डी.ए. सरकार में बिहार देश में तेज गति से निवेश प्रस्ताव हासिल करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2005 से 2008 तक बिहार के गन्ना उद्योग विभाग में मेरे मंत्रित्व काल में "ईख आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम" बिहार विधान सभा द्वारा संशोधित करते हुए गन्ने की रस से सीधे इथेनॉल उत्पादन के संबंध में स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित किया था, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से यह कार्यान्वित नहीं हो पाया। मेरे ही कार्यकाल में बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों के पुनर्प्रवर्तन(Revival) की कार्ययोजना बनी थी, जिसके फलस्वरूप लौरिया एवं सुगौली चीनी मिल को वर्ष 2008 में एच.पी.सी.एल.(HPCL) द्वारा संचालित करने का निर्णय हुआ।

अतः अनुरोध है कि मिथिला क्षेत्र में इथेनॉल उत्पादन के अपार संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तेल कम्पनियों के द्वारा मिथिला में बंद पड़े चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने हेतु समुचित विचार करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 23.9.21

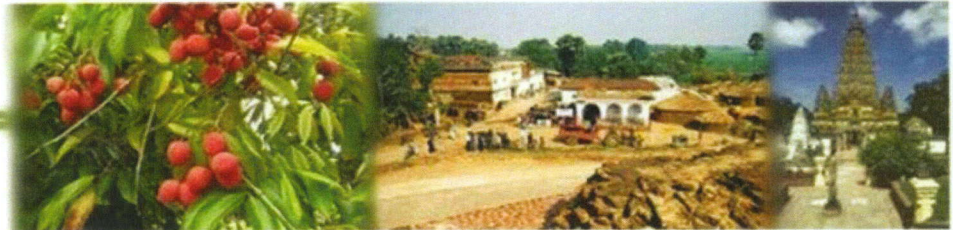
ईमेल—mla-jipur-bih@nic.in

संलग्न—यथोक्त।

सेवा में,

श्री हरदीप सिंह पूरी जी,
माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

<http://bihartoday.blogspot.com>



Wednesday, April 19, 2006

Ethanol-doped-petrol may fuel Bihar sugarcane industry

Patna: Use of ethanol-doped-petrol will revive Bihar's sugarcane industry and generate rural jobs if the central government allows its use and supply, said the state's Minister for Sugarcane Development Nitish Mishra. "It (ethanol-doped-petrol) will certainly help to revive the sugarcane industry because more cultivation and production will take place to meet the demand for the ethanol blend petrol," Mishra said here. Hundreds of sugarcane farmers and sugar mills going through a bad phase may be directly benefited by the use of ethanol-doped-petrol. "The state government will make a formal request soon to the central government to allow use of ethanol-doped-petrol," a state government official said. This will also attract investors to set up new sugar mills in the state, he added. Ethanol is a liquid alcohol made directly or indirectly from sugarcane. Ethanol is also a renewable source of energy made by fermenting any biomass high in carbohydrates. It is most commonly produced from field corn and sugarcane, but is also made from other grains. The government aims to revive all 15 of the closed state-owned sugar mills to generate adequate income for over 500,000 sugarcane farmers. In a bid to encourage investors, the state has also announced incentives for setting up new sugar mills. A few years ago, India joined the race for alternative energy sources and use of ethanol blend petrol. It decided to allow five percent of ethanol mixing with petrol, which is likely to be increased by 10 percent later. Currently, nine states and four union territories undertake ethanol doping, where the requirement is limited to only 345 million litres. In the world market, Brazil - one of the largest sugarcane producers - uses ethanol blend petrol. The US is the largest single consumer of ethanol.

=====

RANJAN RITURAJ SINH

Central directive makes Bihar lose Rs 14, 000 cr in proposals

Patna, May 13 (PTI) A central directive that prohibits production of ethanol from sugarcane juice has dealt a severe blow to Bihar government's plan to develop the state as an ethanol hub with five investment proposals amounting to Rs 14,000 crore lost.

The insertion of explanation (3) in clause 3 (sub-clause in the sugarcane (control) amendment order, 2007 of the Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution that came into effect from December 28 has prevented Bihar from taking up these proposals, official sources said.

Explanation (3) states: 'production of ethanol directly from sugarcane juice shall be allowed in case of sugar factories only'.

The Centre's order led to the state losing five major investment proposals through which 15 new sugarcane juice-to-ethanol manufacturing facilities were to be set up in Bihar.

Bihar State Industrial Promotion Board (BSIPB) had approved these projects and cabinet sanction for all but three had also been obtained, the sources said.

It was during Mishra's 28-month tenure as sugarcane minister that the state government decided to allow direct production of ethanol from sugarcane juice through an amendment to the Sugarcane Regulation and Supply Act, 1981 in March, 2007.

"The central government order has negated that move. Our efforts to develop Bihar as an ethanol hub has suffered a setback," Mishra said.

The proposal by M/s Indian Gasohol Ltd (Erode, Tamil Nadu) to establish 10 ten units of 100 per cent export oriented ethanol plants in various parts of Bihar, having a total capacity of five million tonne at investment of Rs 13,557.00 crore, could not be entertained by the state government because of the Centre's decision, the sources said.

Three other units proposed by a Poland-based NRI under the banner of M/s Braj Industries Pvt Ltd would also be affected, they said.

The ethanol manufacturing units, each involving an investment of Rs 82 crore, were to be set up at Purnea, Sahpur-Kamal in Begusarai and another in Supaul, sources said.

M/s S S Infrastructure Private Limited (Darbhanga) had secured approval for investing Rs 95.04 crore for an ethanol plant at Sukhait in Jhanjharpur block of Madhubani.

Many investors had lined up to establish direct sugarcane-to-ethanol production facilities because such units made better financial sense in the context of Centre's plan to lace petro-fuels with a higher percentage of ethanol, Mishra added.